एमएसएमई इकाइयों का होगा पर्यावरण ऑडिट

वर्ष 2030 तक पर्यावरण संबंधी मानकों को पूरा करना बड़ी चुनौती, नई के साथ पुरानी इकाइयों को पैसे देगा विभाग

अभिषेक गुप्ता

लखनऊ। एमएसएमई इकाइयों को ईको फ्रेंडली बनाने के लिए उनका 'पर्यावरण ऑडिट' कराया जाएगा। इस पर आना वाले खर्च का 75 फीसदी प्रदेश सरकार देगी। ऑडिटर जिन उपकरणों को लगाने की सिफारिश करेगा, उन पर भी 20 लाख रुपये की मदद सरकार करेगी। उद्योगों की इमारत को भी ग्रीन रेटिंग दी जाएगी। इस पर आने वाले खर्च का 50 फीसदी सरकार देगी। इस कवायद का मकसद यूपी की इकाइयों को ग्लोबल प्लेटफॉर्म पर ब्रांडिंग और ईको फ्रेंडली बनाना है। इससे निर्यात में कम से कम 20 फीसदी का इजाफा होगा।

एमएसएमई को शेयर बाजार में उतारने के लिए अलग से मदद

इकाइयों के सामने पूंजी संकट बड़ी समस्या है। इसे दूर करने के लिए बैंकों से लोन प्रक्रिया को आसान बनाया जा रहा है। वहीं, शेयर बाजार के जरिये पूंजी जुटाने के लिए उन्हें तैयार किया जाएगा। इसके लिए फैसिलिटेशन एजेंसी नामित की जाएगी। स्टॉक एक्सचेंज के जरिये इक्विटी पूंजी जुटाने पर आने वाले खर्च का 20 फीसदी (अधिकतम पांच लाख रुपये) प्रदेश सरकार की तरफ से दिए जाएंगे।

2030 तक इकाइयों को पर्यावरण संबंधी मानकों के अनुरूप खुद को तैयार करना है। यह उनके लिए बड़ी चुनौती है, क्योंकि औसतन 50 करोड़ रुपये टर्नओवर वाली एक इकाई को पर्यावरण मानकों के अनुरूप खुद को तब्दील करने में कम से कम एक करोड़ खर्च करने होंगे।

इसके लिए एमएसएमई विभाग सामूहिक प्लांट लगाने में दस करोड़ तक की मदद देगा। ये मदद वेस्ट मैनेजमेंट सिस्टम, कॉमन एफ्लुएंट ट्रीटमेंट प्लांट, कॉमन मल्टीपल इफेक्ट इवेपोरेटर, कॉमन स्प्रे ड्रायर और बायो डिग्रेडेबिल पर दी जाएगी। जीरो लिक्विड डिस्चार्ज प्लांट लगाने पर अधिकतम 75 लाख रुपये दिए जाएंगे। दस एमएसएमई द्वारा संयुक्त रूप से एक ब्वॉलर लगाने पर भी 50 लाख रुपये का प्रावधान रखा गया है।

एमएसएमई विभाग के अपर मुख्य सचिव अमित मोहन प्रसाद के मुताबिक छोटी इकाइयों को भरपूर प्रोत्साहन दिया जा रहा है। क्लीन उत्पादन तकनीक जैसे कच्चे माल को ठीक से रखने, पानी व बिजली की खपत में कमी, प्रदूषण नियंत्रण उपकरण आदि पर आने वाले खर्च पर 20 लाख रुपये तक उद्यमी को विभाग देगा। इमारत को भी ईको फ्रेंडली प्रमाणित करने के लिए इंडियन ग्रीन बिल्डिंग काउंसिल से ग्रीन रेटिंग लेने पर 2.5 लाख रुपये विभाग देगा। पर्यावरण प्रबंधन प्रयोगशाला बनाने पर 10 लाख रुपये मिलेंगे।

प्रदेश में सभी एमएसएमई क्लस्टर को एक तकनीकी और एक प्रबंध संस्थान से जोड़ा जा रहा है। ये संस्थान मिनी सेंटर ऑफ एक्सीलेंस स्थापित करेंगे। इनका उद्देश्य छोटे उद्यमियों को हाईटेक बनाना, उनके खर्च को कम करना और उत्पादों को बाजार के हिसाब से गुणवत्तायुक्त बनाना होगा। उद्यमी अपने कर्मचारियों को जरूरत के हिसाब से प्रशिक्षण दें, इसके खर्च का बड़ा हिस्सा भी एमएसएमई विभाग देगा। इस मद में एक कर्मचारी पर आने वाले खर्च का 75 फीसदी या अधिकतम 50 हजार रुपये उद्यमी को दिया जाएगा।